



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 508]
No. 508]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 4, 2003/ज्येष्ठ 14, 1925
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 4, 2003/JYAISTHA 14, 1925

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2003

का.आ. 650(अ).—यतः केन्द्र सरकार ने विधि-विरुद्ध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 23 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) सं० का०आ० 1224 (अ०) के तहत नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी) को विधि-विरुद्ध संगठन घोषित किया है;

और यतः केन्द्र सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 20 दिसम्बर, 2002 की अधिसूचना का०आ० 1340 (अ०) के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मनमोहन सरीन की अध्यक्षता में विधि-विरुद्ध गतिविधियां (निवारण) अधिकरण का गठन किया है;

और यतः केन्द्र सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना को 20 दिसम्बर, 2002 को उक्त अधिकरण को न्यायमूर्ति के प्रयोजनार्थ भेजा कि क्या उक्त संगठन को विधि-विरुद्ध संगठन के रूप में घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं;

और यतः उक्त अधिकरण ने, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 20 मई, 2003 को आदेश दिया जिसमें उक्त अधिसूचना में की गई घोषणा की पुष्टि की गई है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अधिकरण के उक्त आदेश को प्रकाशित करती है, अर्थात् :-

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण के समक्ष

नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) को विधि-विरुद्ध संगम घोषित करने के संबंध में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 23.11.2002 की राजपत्र अधिसूचना सं.का.आ.1224(अ) के मामले में तथा :

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 के अंतर्गत संदर्भ के मामले में :-

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन

उपस्थित व्यक्ति :

श्री संजय जैन, केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता,
सुश्री कृष्ण शर्मा तथा सुश्री मेघाली बर्ठाकुर, असम राज्य की अधिवक्ता,
श्री बलराम चोपड़ा, अधिकरण के रजिस्ट्रार ।

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण के समक्ष

नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट ऑफ बोडोलैंड के संदर्भ में :

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनमोहन सरीन

आदेश

1. केंद्र सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (जिसे इसमें इसके बाद अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई दिनांक 23.11.2002 की अधिसूचना सं 1224(अ) के तहत नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट ऑफ बोडोलैंड (संक्षिप्त में एन0डी0एफ0बी0) को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया था । केन्द्र सरकार की यह भी राय थी कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके एन0डी0एफ0बी0 को तत्काल प्रभाव "विधिविरुद्ध संगम" घोषित किया जाना आवश्यक है । केन्द्र सरकार ने इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई दिनांक 20.12.2002 की एक दूसरी अधिसूचना के तहत मेरी अध्यक्षता में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण का गठन किया ताकि यह न्याय-निर्णय किया जा सके कि क्या एन0डी0एफ0बी0 को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं ।
2. अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत एन0डी0एफ0बी0 को नोटिस जारी किए जाने का निदेश दिया गया था । इन नोटिसों को दैनिक राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाने तथा रेडियों एवं टेलीविजन पर प्रसारण के द्वारा भी इनकी सूचना दिए जाने का निदेश दिया गया था । इन नोटिसों की सूचना असम में, जहां एन0डी0एफ0बी0 का संगठन मौजूद है, जिला मजिस्ट्रेटों/तहसीलदारों के कार्यालयों के सूचना-पट्टों पर लगाने का भी निदेश दिया गया था । उक्त नोटिसों में प्रभावित संगठन से यह अपेक्षा की गई थी कि वह इस नोटिस के दिए जाने या इसके प्रकाशन/प्रसारण की तारीख से 30 दिन के भीतर यह बताए कि क्यों न एन0डी0एफ0बी0 को विधिविरुद्ध संगम घोषित कर दिया जाए तथा क्यों न इस घोषणा की अभिपुष्टि करने संबंधी आदेश जारी कर दिया जाए ।

3. उन नोटिसों, जिनको अधिकरण द्वारा जारी किए जाने का निदेश दिया गया था, का गुवाहाटी के आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा प्रसारण किया गया था तथा इन्हें दिनांक 5.2.2003 को राष्ट्रीय दैनिक "इण्डियन एक्सप्रेस" में, दिनांक 5.2.2003 को ही "असम ट्रिब्यून" में और दिनांक 4.2.2003 को "अमर असम" में प्रकाशित किया गया था। प्रकाशित उद्धरणों सहित तामील किए जाने संबंधी शपथ-पत्र भारत संघ की ओर से श्री रामफल, अवर सचिव, गृह मंत्रालय तथा असम राज्य सरकार की ओर से श्री एस0के0 राय, संयुक्त सचिव, असम सरकार द्वारा दायर किए गए थे। तदनुसार तामील किए जाने संबंधी कार्यवाई पूरी कर ली गई। एन0डी0एफ0बी0 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः दिनांक 11.3.2003 के आदेश के तहत केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को अपनी-अपनी ओर से शपथ-पत्रों के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।

4. अधिकरण को यह न्याय-निर्णय करने के लिए अधिदेश दिया गया है कि क्या एन0डी0एफ0बी0 को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं तथा उसे तत्काल प्रभाव से ऐसा करने के लिए अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के परंतुक के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने का भी अधिदेश दिया गया है।

5. केन्द्र सरकार ने अधिकरण के समक्ष इस संदर्भ के प्रयोजनार्थ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी दिनांक 23.11.2002 की अधिसूचना दायर की जिसमें एन0डी0एफ0बी0 को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया है। इस अधिसूचना के साथ एक सारांश भी था जिसमें एन0डी0एफ0बी0 के लक्ष्य और उद्देश्य तथा वे तथ्य भी उल्लिखित थे जिन पर धारा 3 के अंतर्गत दी गई अधिसूचना के कारण आधारित थे जैसा कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) नियम, 1968 (जिसे इसमें इसके बाद "नियम" कहा गया है) के नियम 5 के अंतर्गत अपेक्षित है।

6. दायर किए गए सारांश के अनुसार एन0डी0एफ0बी0 को 3.4.1986 को गठित किया गया था जिसका सुस्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य सशस्त्र संघर्ष द्वारा असम के बोडोवासी क्षेत्रों को भारत से आजाद करना और एक स्वतंत्र तथा संप्रभु बोडोलैंड बनाना था। एन0डी0एफ0बी0 के संविधान की एक प्रति भी रिकार्ड पर प्रस्तुत की गई। प्रदर्श पी0 डब्ल्यू0 1/ए I के अनुसार एन0डी0एफ0बी0 के सिद्धांत और विचारधाराएं हैं—(i) बोडोलैंड को भारतीय विस्तारवाद तथा आधिपत्य से स्वतंत्र कराना, (ii) बोडो राष्ट्र को उपनिवेशवादी शोषण, दमन तथा आधिपत्य से मुक्त कराना, (iii) स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए एक लोकतांत्रिक, समाजवादी समाज स्थापित करना, तथा (iv) बोडोलैंड की अखंडता और प्रभुसत्ता को बनाए रखना।

एन0डी0एफ0बी0 को दिनांक 23.11.1992 को अधिनियम के अंतर्गत एक विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया था। बाद में, दिनांक 23.11.1994, 23.11.1996, 23.11.1998 तथा 23.11.2000 को इसे पुनः प्रतिबंधित किया गया था और अब इसे दिनांक 23.11.2002 को जारी की गई वर्तमान अधिसूचना द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।

7. पैरा 6 में उल्लिखित किए गए अनुसार केन्द्र और असम राज्य सरकारों ने मामले के समर्थन में निम्नलिखित व्यक्तियों के शपथ-पत्रों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं :

- पी0डब्ल्यू0 1. श्री एस0के0 राय, संयुक्त सचिव, असम सरकार, राजनीतिक विभाग, गुवाहाटी ।
- पी0डब्ल्यू0 2. श्री प्रतुल चौधरी फुकन, पुलिस अधीक्षक, स्पेशल ऑपरेशन यूनिट, असम सरकार, दिसपुर, गुवाहाटी ।
- पी0डब्ल्यू0 3. श्री बी0बी0 चेतरी, पुलिस अधीक्षक, जिला बारपेटा ।
- पी0डब्ल्यू0 4. श्री खबीर अहमद, पुलिस अधीक्षक, जिला दारांग ।
- पी0डब्ल्यू0 5. श्री आर0 विजय कृष्ण, पुलिस अधीक्षक, जिला कोकराझार ।
- पी0डब्ल्यू0 6. श्री सत्येन गोगोई, पुलिस अधीक्षक, सोनितपुर, तेजपुर ।
- पी0डब्ल्यू0 7. श्री एम0 अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक, कामरूप (देहात) ।
- पी0डब्ल्यू0 8. श्री अमरेन्द्र बोरगोहाई, पुलिस अधीक्षक, जिला बोंगाईगांव ।
- पी0डब्ल्यू0 9. श्री पी0सी0 बोरोदोलोई, पुलिस अधीक्षक, धुबरी ।
- पी0डब्ल्यू0 10. श्री शरत कुमार फुकन, पुलिस अधीक्षक, नलबाड़ी ।
- पी0डब्ल्यू0 11. श्री ए0के0 गोयल, निदेशक (एन ई), गृह मंत्रालय

8. केन्द्र सरकार का यह दावा है कि एन0डी0एफ0बी0 अपना गठन होने के बाद से ही दारांग, सोनितपुर, कोकराझार, बोंगाईगांव, नलबाड़ी, बारपेटा, धुबरी तथा कामरूप जिलों में बोडो बहुल क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आतंकवादी तथा विध्वंसक कार्यकलापों में लिप्त रहा है जिससे गैर-जनजातीय लोगों के बीच काफी डर तथा असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई है तथा बोडो लोग भी एन0डी0एफ0बी0 की अलगाववादी विचारधारा के विरुद्ध हैं । प्रतिबंध की अवधि के दौरान भी, एन0डी0एफ0बी0 सेना/पुलिस/सुरक्षा बलों के कार्मिकों तथा कानून का पालन करने वाले नागरिकों पर हमला करने और उनकी हत्या करने, सुरक्षा बलों के कार्मिकों से शस्त्र और गोलाबारूद लूटने, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने सहित अपनी आतंकवादी हिंसा के कार्यकलापों को और अधिक बढ़ाकर अपनी अलगाववादी गतिविधियों को जारी रखे हुए है । ऐसा समझा गया है कि एन0डी0एफ0बी0 ने बंगलादेश में खगरासारी जिले के अंदर और असम के दारांग, नलबाड़ी, कोकराझार और बारपेटा जिलों के सामने भूटान में कई कैप स्थापित किए हैं । इन स्थानों पर उसने अपने संवर्गों के एक हजार से अधिक सदस्यों को प्रशिक्षित किया है । यह बताया गया है कि भूटान सरकार के इस निर्णय के बाद कि उसकी

जमीन से किसी भी आतंकवादी संगठन को अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, वर्ष, 2000 के दौरान एन0डी0एफ0बी0 उसका विरोधी हो गया। इसके बाद उसने राज्य में हत्या की कई वारदातों की जिनमें भूटानी मूल के एक नेपाली सहित 13 भूटानी लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या करना शामिल है। ट्रकों को भी आग लगायी गई।

9. 23.11.2000 से 30.6.2002 की अवधि के दौरान हिंसा की 327 घटनाएं घटीं जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे असम राज्य से एन0डी0एफ0बी0 के लोगों द्वारा की गई थीं। एन0डी0एफ0बी0 के आतंकवादियों ने 275 लोगों की हत्या की जिनमें से 24 लोग सेना/पुलिस और सुरक्षा कार्मिक थे तथा 251 सिविलियन थे। 147 व्यक्ति घायल हुए। चाय बागान के 43 कार्मिकों का अपहरण किया गया जिनमें से 22 को बाद में छोड़ दिया गया, 11 लोगों को मार दिया गया और 10 व्यक्ति अभी भी उनकी कैद में हैं। एन0डी0एफ0बी0 के संवर्गों ने अत्याधुनिक हथियार प्राप्त किए हैं और ये हथियार अभी भी उनके पास हैं तथा वे अभी भी नए लोगों की भर्ती कर रहे हैं। एन0डी0एफ0बी0 बोडो क्षेत्रों के मुसलमानों, बंगाली हिन्दुओं, नेपालियों और आदिवासी आप्रवासियों की हत्या करने की नीति अपना रहा है ताकि वह इन लोगों को ये क्षेत्र छोड़ने पर विवश कर सके। केन्द्र सरकार का यह विचार है कि एन0डी0एफ0बी0, यू0एल0एफ0ए0 तथा अन्य आतंकवादी और पृथक्तावादी संगठनों के साथ गठबंधन बना रहा है ताकि भारत की संप्रभुता और अखंडता को छिन्न-भिन्न किया जा सके।

10. 23.11.2000 से 30.6.2002 के दौरान एन0डी0एफ0बी0 ने निम्नलिखित हिंसात्मक वारदातों की हैं:

- i. 275 व्यक्तियों की हत्या।
- ii. अपनी वारदातों के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से फिरौती के लिए अपहरण और लूट-खसौट।
- iii. नए संवर्गों की भर्ती।
- iv. गुप्त रूप से पत्रिकाएं छापी जिनमें अपने लक्ष्यों का बखान किया तथा केन्द्र सरकार के तथाकथित शोषण की भर्त्सना की।
- v. अपने संवर्गों को सरकारी तंत्र का पता लगाने और उस पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया।
- vi. गैर-बोडो लोगों में दहशत और असुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से हत्याकांड और नृजातीय हिंसा की ताकि उन्हें बोडो क्षेत्रों से बाहर जाने पर बाध्य किया जा सके।
- vii. देश की सीमा पार कैप और छिपने के स्थान स्थापित करना और भारत-विरोधी तत्वों से शस्त्र और दूसरी तरह की सहायता प्राप्त की।

11. केन्द्र सरकार की ओर से श्री ए0के0 गोयल, निदेशक, (एन ई) पी0डब्ल्यू0 11/1 द्वारा दायर हलफनामे में, जो एक पर्याप्त हलफनामा है तथा जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा एन0डी0एफ0बी0 का प्रोफाइल दिया गया है, इसके उद्देश्यों, प्रमुख पदाधिकारियों तथा हिंसा का विस्तृत उल्लेख किया गया है तथा इसके विदेशों के साथ एवं पूर्वोत्तर के अन्य अलगाववादी संगठनों के साथ संबंधों का भी उल्लेख किया गया है। हलफनामे में इसकी वारदातों के क्षेत्रों, अत्याधुनिक हथियार प्राप्त करने, आप्रवासियों अर्थात् बोडो-क्षेत्र में रहने वाले मुसलमानों, बंगालियों, हिन्दुओं, नेपालियों तथा आदिवासियों की हत्याओं का ब्यौरा दिया गया है जो उन्हें इस क्षेत्र को छोड़ने पर मजबूर करने के उद्देश्य से की गई थी। हलफनामे के अनुलग्नक-I में प्राप्त हुई आसूचना रिपोर्टों का भी उल्लेख किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि रंजन डाइमरी, गोविदा बासुमतरी आदि जैसे

एन0डी0एफ0बी0 के अधिकांश नेता भूटान या बंगलादेश में स्थित कैपों में थे जहां से वे वारदातें करने के निदेश दे रहे थे ।

12. श्री एस0के0 राय, संयुक्त सचिव, असम सरकार, गृह और राजनीति विभाग के शपथ-पत्र की जांच की गई थी और उन्होंने अपने हलफनामे पी0डब्ल्यू0 1/1 को सिद्ध किया । श्री एस0के0 राय ने साक्ष्य दिया कि चूंकि राज्य की सुरक्षा करना और गैर-कानूनी संगठनों से निपटना उनकी जिम्मेदारी है, अतः आसूचना रिपोर्टें प्राप्त करना उनका सरकारी कर्तव्य है । एन0डी0एफ0बी0 की गतिविधियों के संबंध में पुलिस अधीक्षकों और जिलों तथा पुलिस मुख्यालयों से सूचना प्राप्त की गई थी और आपराधिक तथा गैर-कानूनी गतिविधियों के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़ों को संग्रहित एवं समेकित किया गया था । प्रदर्श पी0डब्ल्यू0 1/ए 1 में एन0डी0एफ0बी0 के संविधान की प्रति दी गई है। प्रदर्श पी0डब्ल्यू0 1/ए 2 में 23.11.2000 से 30.6.2002 की अवधि के दौरान जिला-वार हत्याओं, अपहरणों, हथियार छीनने के सांख्यिकी आंकड़ों का संकलन दिया गया है। प्रदर्श पी0डब्ल्यू0 1/ए 2 के अनुसार 23.11.2000 से 30.6.2002 की अवधि के दौरान 275 व्यक्ति मारे गए थे जिनमें से 251 सिविलियन तथा 24 पुलिस/सुरक्षा बलों के कार्मिक थे । व्यपहरण की 44 घटनाएं हुई, लगभग 147 व्यक्तियों को एन0डी0एफ0बी0 संवर्ग ने घायल किया था । उनके पर्यवेक्षण में घटनाओं के ब्यौरे भी संकलित किए गए हैं । प्रतिबंध की अवधि के दौरान किए गए अलगाववादी क्रियाकलाप के ब्यौरे देते हुए प्रदर्श पी0डब्ल्यू0 1/3 नोट तैयार किया गया है । इस नोट में 185 घटनाओं का विवरण भी है। उन्होंने साक्ष्य दिया कि प्राप्त तथा तदनुरूप संग्रहित सूचना के आधार पर राज्य सरकार ने असम सरकार के सचिव तथा आयुक्त का दिनांक 9.8.2002 का पत्र प्रस्तुत किया जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि एन0डी0एफ0बी0 पर प्रतिबंध जारी रखा जाए क्योंकि उनकी आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियां जारी हैं । उन्होंने साक्ष्य दिया कि प्रदर्श पी0डब्ल्यू0 1/ए 2, ए 3, ए 4 और ए 5 में वर्णित सूचना एवं विवरण अनुरक्षित रिकार्ड और आसूचना इनपुटों तथा विशेष शाखा से प्राप्त सूचना के आधार पर सही हैं ।

13. पी0डब्ल्यू0 2, श्री प्रतुल चन्द्र फूकन, पुलिस अधीक्षक, विशेष आपरेशन एकक, ने अपना हलफनामा पी0डब्ल्यू0 2/1 सिद्ध कर दिया । उन्होंने साक्ष्य दिया कि सूचना एकत्र करना तथा उसे असम सरकार को भेजना उनकी जिम्मेदारी है । अन्य आसूचना एजेंसियों नामशः केन्द्र सरकार की आई0बी0 तथा एस0एस0बी0 से प्राप्त जानकारी का उन्होंने संग्रहण तथा विश्लेषण किया तथा इसे जिला इकाइयों को भेजा । उन्होंने साक्ष्य दिया कि एन0डी0एफ0बी0 स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि के बहिष्कार का आह्वान करने जैसी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा है । उन्होंने साक्ष्य दिया कि एन0डी0एफ0बी0 असम के निचले क्षेत्रों जैसे दारंग, नलबाड़ी, कोकराझार, बारपेटा, बोंगाईगांव, धुबरी में सक्रिय रहा है । एन0डी0एफ0बी0 हत्या, धन-उगाही व्यपहरण, विस्फोट करना आदि में संलिप्त रहा है । एन0डी0एफ0बी0 के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति बोडो आधिपत्य वाले क्षेत्रों के युवकों में से की जाती थी । एन0डी0एफ0बी0 ने कई लोगों को अपना निशाना बनाया है और यह प्रायः नृजातीय अपराधों में लिप्त रहता है जिनमें गैर बोडो लोगों को निशाना बनाया जाता है । उन्होंने बताया कि उनके कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान, बंगलादेश और भूटान के शिविरों में प्रशिक्षित किया जाता है । एन0डी0एफ0बी0 की कार्यप्रणाली की कुछ विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इसके कार्यकर्ताओं और सदस्यों को उनके जनजातीय चेहरों से पहचाना जा सकता है । उन्होंने सामान्यतः छोटे-छोटे समूहों में अत्याधुनिक तथा परिष्कृत हथियारों का प्रयोग कर अपना कार्य किया है । समय-समय पर

एन0डी0एफ0बी0 की संलिप्तता गिरफ्तार व्यक्तियों से, चश्मदीद गवाहों से या घटना में बच निकले लोगों से या बाद में छोड़ दिए गए अपंग व्यक्तियों के बयानों से सिद्ध हो जाती है। उन्होंने एन0डी0एफ0बी0 द्वारा मारे गए लोगों तथा अन्य हिंसक घटनाओं की जानकारी भी दी।

14. श्री बी0बी0 चेतरी, पुलिस अधीक्षक, बारपेटा जिला ने अपना हलफनामा पी0डब्ल्यू0 3/1 सिद्ध कर दिया है। एन0डी0एफ0बी0 के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का वर्णन करने के अलावा उन्होंने बताया कि एन0डी0एफ0बी0 को ज्यादातर लूटखसोट से धन प्राप्त होता है। उन्होंने विस्तृत वाद सं0 259/2001 के संबंध में साक्ष्य दिया जिसमें 150 उग्रवादियों ने अत्याधुनिक तथा परिष्कृत हथियारों, हथगोलों से लैस होकर पुलिस चौकी पर कब्जा करने के लिए लब्दानगुरी पर हमला किया था। पुलिस चौकी को आग लगा दी गई तथा दो पुलिस कर्मियों की जानें गई थी। राकेट लांचर के जले ढक्कन तथा चीनी हथगोले के एक ढक्कन के साथ एन0डी0एफ0बी0 का झंडा बरामद हुआ था। इस हमले में दो उग्रवादी मारे गए थे जिनकी शिनाख्त जासेफ उर्फ मोहन दैमारी तथा मिठिंगा दैमारी के रूप में हुई। ये दोनों एन0डी0एफ0बी0 के नेता थे।

15. खबीर अहमद, पुलिस अधीक्षक, दारंग जिला ने भी अपना हलफनामा प्रदर्श पी0डब्ल्यू0 4/1 सिद्ध कर दिया है और कई विस्तृत मामलों के संबंध में अपने साक्ष्य दिए हैं। एक मामले में 5 व्यक्तियों को छुड़वाया गया। जांच पड़ताल के दौरान स्पष्ट हुआ कि अपहरणकर्ता एन0डी0एफ0बी0 के थे और उन्होंने उनको भूटान में स्थित एक शिविर से दूसरे शिविर में अंतरित कर दिया था।

16. श्री आर0 विजय कृष्ण, पुलिस अधीक्षक, कोकराझार जिला ने अपना हलफनामा प्रदर्श पी0डब्ल्यू0 5/1 सिद्ध कर दिया और अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में अभिलेख के आधार पर साक्ष्य दिया। उन्होंने साक्ष्य दिया कि एन0डी0एफ0बी0 मुख्यतः हत्याओं, जबरन धन-वसूली, तथा पुलिस/अर्द्ध-सैनिक बलों तथा सुरक्षा बलों पर हमला करने में संलिप्त है। उन्होंने 30.6.2001 को हुई घटना के संबंध में साक्ष्य दिया जब एन0डी0एफ0बी0 उग्रवादी दोस्ती के बाजार में आए और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई एवं बम विस्फोट किए जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। फिरौती के लिए दो लोगों का अपहरण भी किया गया। अपहृत व्यक्तियों से धन ऐंठने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था जिन्होंने बताया था कि उन्हें जंगल में रखा गया था और अपहरणकर्ता एन0डी0एफ0बी0 संवर्गों से संबंधित थे। उन्होंने यह भी बयान दिया कि एन0डी0एफ0बी0 के उग्रवादियों ने दो व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी, उन्हें यह शक था कि वे पुलिस के मुखबिर थे। श्री आर0 विजय कृष्ण ने यह भी बयान दिया कि ऐसे मामलों, जिनमें अपराध करने में एन0डी0एफ0बी0 संवर्ग की संलिप्तता के निश्चित और पक्के साक्ष्य उपलब्ध हैं, की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनके आधार पर अपराधों में एन0डी0एफ0बी0 का हाथ होने और उसकी संलिप्तता सिद्ध की जा सकती है। ये विशेषताएं हैं (i) बोडो समुदाय के प्रभुत्व वाले इलाकों में अपराध की घटनाएं होना जहां एन0डी0एफ0बी0 उग्रवादियों को आश्रय और सहायता दी जाती है; (ii) आकृति और संरचना संबंधी विशेषताएं जो विशेष रूप से बोडो समुदाय के लोगों में ही पाई जाती हैं; (iii) ए0के0 सीरीज असाल्ट राइफलों, राकेट लांचर और रिमोट से चालित विस्फोटक उपकरण (आई0ई0डी0) जैसे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल जहां एन0डी0एफ0बी0 कार्मिकों द्वारा किए जाने वाले हमलों की अपनी विशिष्ट विशेषता है; (iv) एन0डी0एफ0बी0 के पक्ष में आमतौर पर नारे लगाने की और उनके झंडे और पर्वे छोड़ने की प्रथा।

उन्होंने यह बयान दिया कि सुरक्षा बलों ने एन0डी0एफ0बी0 पर काबू पाने में सफलता प्राप्त करने के लिए संगत उपाय किए थे । तथापि, किसी भी प्रकार की उदरता बरतने से एन0डी0एफ0बी0 पुनर्गठित तथा सुदृढ़ हो सकता है ।

17. श्री सत्येन गोगोई, पुलिस अधीक्षक, सोनितपुर, तेजपुर ने अपने शपथ-पत्र प्रदर्श पी0डब्ल्यू0 6/1 को सिद्ध किया । उन्होंने यह बयान दिया कि उनके जिले में एन0डी0एफ0बी0 एक प्रमुख विधिविरुद्ध संगठन था, जो बहुत सक्रिय था और उसके उपरान्त सक्रियता में उल्फा का स्थान है । उन्होंने शपथ-पत्र में बताए गए विस्तृत मामलों के बारे में भी साक्ष्य दिया । मामले के ब्यौरे के अनुसार एन0डी0एफ0बी0 उग्रवादियों ने एक गश्ती दल पर स्वचालित हथियारों और हथगोलों से हमला किया । बाद में अज्ञात शवों की पहचान कल्प बोडो और मोनेश्वर बोसुमतारी के रूप में की गई । यह पहचान उनके निकट संबंधियों द्वारा की गई जो बोडो के जाने-माने सदस्य थे । उन्होंने दिनांक 30.6.2001 को मामला संख्या 76/2000 के बारे में यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि जब परिमल पाल का अपहरण कर लिया गया था और वह बीमार पड़ गए थे तो उनके इलाज के लिए एन0डी0एफ0बी0 के कार्मिक एक डाक्टर को बुलाकर लाए थे ।

18. इसी प्रकार श्री एम0 अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक, कामरूप, श्री अमरेन्द्र बोरगोहाई, पुलिस अधीक्षक, बोंगाईगांव जिला, श्री पी0सी0 बोरोदोलोई, पुलिस अधीक्षक, धुबरी और श्री शरत कुमार फुकन, पुलिस अधीक्षक, नलबाड़ी ने साक्ष्य के तौर पर दायर अपने-अपने शपथ-पत्रों को सिद्ध किया और अपने-अपने शपथ-पत्रों में उल्लिखित विस्तृत मामलों के रिकार्ड प्रस्तुत करके ब्यौरे दिए हैं । उन विस्तृत घटनाओं का वर्णन किया गया है जिनमें एन0डी0एफ0बी0 कार्मिकों ने हत्याएं की तथा परिष्कृत हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी की और सुरक्षा बलों पर हमले करने एवं सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लिप्त रहे । एन0डी0एफ0बी0 कार्मिकों पर आरोपित उक्त घटनाओं के साक्ष्य तथा आधारों को भी अधिकरण के समक्ष प्रकट तथा प्रस्तुत किया गया । जबरन धन वसूली के एक मामले में एन0डी0एफ0बी0 के क्रांतिकारी कोष के लिए बोडोलैंड कर/अंशदान के रूप में 5 करोड़ रुपए का भुगतान करने की मांग संबंधी मूल पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

19. केन्द्र सरकार की ओर से श्री ए0के0 गोयल, पी0डब्ल्यू0 11 द्वारा साक्ष्य के रूप में दायर शपथ-पत्रों, जिनके साथ संलग्नक भी हैं, तथा श्री एस0के0 रॉय, संयुक्त सचिव, असम, पी0डब्ल्यू0 1 के शपथ पत्र और मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए आंकड़ों, सूचनाओं तथा दस्तावेजों एवं रिकार्ड आदि साक्ष्य के रूप में, केन्द्र सरकार, एन0डी0एफ0बी0 तथा उसके सदस्यों की विधिविरुद्ध गतिविधियों को साबित करने में सफल हुई है । असम राज्य में जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साक्ष्य तथा प्रस्तुत रिकार्ड एन0डी0एफ0बी0 तथा उसके सदस्यों द्वारा की गई अधिसंख्यक हत्याओं, आतंकवादी कृत्यों को दर्शाते हैं । केन्द्र तथा राज्य सरकार ने यह साबित कर दिया कि एन0डी0एफ0बी0, जो मूलतः बोडो सुरक्षा बल के रूप में जाना जाता था, को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं । केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत शपथ-पत्रों ने यह दर्शाया है कि असम के बोडो आबादी वाले क्षेत्रों को भारत से मुक्त कराने तथा सशस्त्र विद्रोह के जरिए पृथक तथा स्वतंत्र बोडोलैंड की स्थापना करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एन0डी0एफ0बी0, विधिविरुद्ध गतिविधियों में लिप्त रहा है जिसकी पुष्टि अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से होती है ।

जैसा कि इससे पहले पैरा 11 से 17 तक में चर्चा की गई है, एन0डी0एफ0बी0 (i) आतंक फैलाने तथा भारत की अखण्डता एवं संप्रभुता की रक्षा के लिए तैनात बलों के खिलाफ दुर्भावना प्रदर्शित करने के लिए सुरक्षा बलों, अर्द्ध-सैनिक बलों पर हमले करने/हत्या करने; (ii) बोडो बहुल क्षेत्रों से गैर बोडो लोगों को भगाने, उनकी हत्याएं करने एवं उन्हें भयभीत करने; (iii) एन0डी0एफ0बी0 संवर्ग में भर्ती का विरोध करने पर बोडो लोगों को सजा देने; (iv) शस्त्र आदि की खरीद के लिए राशि इकट्ठा करने हेतु अपहरण तथा जबरन धन वसूली करने; (v) पूर्वोत्तर के राष्ट्र-विरोधी तथा अन्य प्रतिबंधित संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने; (vi) नागरिकों की हत्याएं करने, आगजनी तथा नृजातीय हिंसा करने; और (vii) सीमा पार के शिविरों से अपनी गतिविधियां संचालित करने में संलिप्त रहा है।

20. इसके अतिरिक्त:

- (i) 23.11.2002 से 30.6.2002 की अवधि के दौरान हत्याओं, अपहरण, जबरन धन वसूली तथा आतंकवादी एवं विधिविरुद्ध गतिविधियों की संख्या;
- (ii) विदेशों सहित गोपनीय स्रोतों से शस्त्र, गोलाबारूद तथा विस्फोटकों की प्राप्ति;
- (iii) भूटान, बांग्लादेश में प्रशिक्षण शिविरों की स्थापना तथा
- (iv) सेना/पुलिस, सुरक्षा बलों पर होने वाले लगातार हमले किए जाने, जो सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अपनी अलगाववादी गतिविधियों को जारी रखने की एन0डी0एफ0बी0 की योजना के स्पष्ट सूचक हैं, को ध्यान में रखते हुए एन0डी0एफ0बी0 पर एक विधिविरुद्ध संगठन के रूप में शीघ्र प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता थी ताकि संगठन के सदस्यों को पुनः संगठित होने तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने से रोका जा सके।

इन तथ्यों के परिपेक्ष्य में इस संगठन को तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी संगठन घोषित करने के लिए उपधारा (3) के परन्तुक 3 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग किया जाना पूरी तरह न्यायोचित है। तदनुसार, मेरा भी यह मानना है कि दिनांक 23.11.02 की अधिसूचना सं0 का0आ0 1224(अ) के अनुसार विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अधीन एन0डी0एफ0बी0 को एक गैर कानूनी संगठन घोषित करने के पर्याप्त कारण थे। उक्त अधिसूचना में केन्द्र सरकार द्वारा की गई घोषणा की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है।

[फा. सं. -11011/25/2002 एन ई-IV]

ए.के. गोयल, निदेशक

दिनांक 20 मई 2003

1550 GS/03-2

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th June, 2003

S.O. 650(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), declared the National Democratic Front of Boroland (NDFB) to be an Unlawful association vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 1224 (E), dated the 23rd November, 2002 (hereinafter referred to as the said notification);

And whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 of the said Act, constituted vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 1340 (E), dated the 20th December, 2002, the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal, consisting of Justice Shri Manmohan Sarin Judge of Delhi High Court;

And whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by the Sub-section (1) of Section 4 of the said Act, referred the said notification to the said Tribunal on the 20th December, 2002, for the purpose of adjudicating whether or not there was sufficient cause for declaring the said association as unlawful;

And whereas the said Tribunal, in exercise of the powers conferred by the Sub-section (3) of Section 4 of the said Act, made an order on the 20th May, 2003, confirming the declaration made in the said notification;

Now, therefore, in pursuance of Sub-section (4) of Section 4 of the said Act, the Central Government hereby publishes the said order of the said Tribunal namely: -

BEFORE THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL

In the matter of :

Gazette Notification No. S. O. 1224 (E) dated 23.11.2002, declaring National Democratic Front of Boroland (NDFB) as an unlawful association issued by the Central Government in exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

And in the matter of:

Reference under Section 4 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

Coram :

HON'BLE MR. JUSTICE MANMOHAN SARIN

Present :

Mr. Sanjay Jain, Central Government Standing Counsel Ms. Krishna Sarma and Ms. Meghalee Barthakur, Advocates for State of Assam.

Mr. Balram Chopra, Registrar of the Tribunal.

BEFORE THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL

In re :

National Democratic Front of Boroland

Coram:

Hon'ble Mr. Justice Manmohan Sarin

ORDER

1. The Central Government vide a notification bearing No. 1224(E) dated 23.11.2002, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (hereinafter referred to as "the Act") declared National Democratic Front of Boroland (for short NDFB) as an unlawful association. The Central Government also formed an opinion that it was necessary to declare NDFB as an "Unlawful Association" with immediate effect by invoking the powers conferred under proviso to Sub-section (3) of Section 3 of the Act. The Central Government vide another notification dated 20.12.2002 issued under Sub-section (1) of Section 5 of the Act appointed and constituted me as the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring NDFB as an unlawful association.

2. Notices were directed to be issued to NDFB under Sub-section (2) of Section 4 of the Act. Publication of the notices was also directed in the national daily and local newspapers as well as by broadcasting and telecasting it on radio and television. Notices were also directed to be served by pasting the same on the Notice Board of the offices of the District Magistrates/Tehsildars in Assam having the presence of the association NDFB. The above notices required the affected association to show cause within 30 days from the date of service or publication/broadcast/telecast of the notice as to why NDFB should not be declared an unlawful association and why an order should not be made confirming the declaration.

3. The notices directed to be issued by the Tribunal were broadcast on All India Radio, Guwahati. It was telecast by Doordarshan Kendra, Guwahati and published in the national daily "Indian Express" dated 5-2-2003, "Assam Tribune" dated 5-2-2003 and "Amar Asom" dated 4-2-2003. The affidavits of service were filed on behalf of Union of India, by Sh. Ram Phal, Under Secretary, Ministry of Home Affairs and by Sh. S. K. Roy, Joint Secretary to the Government of Assam on behalf of State Government of Assam, together with the citations as published. Service was, accordingly, complete. None appeared on behalf of the NDFB. The Central Government and State Government were, therefore, directed vide order dated 11.3.2003, to file evidence by way of affidavits on their behalf.

4. The Tribunal has been given the mandate to adjudicate upon whether there is sufficient cause for declaring NDFB as an unlawful association and for exercising the power under proviso of Sub-section (3) of Section 3 of the Act to do so with immediate effect?

5. The Central Government for the purpose of the reference filed before the Tribunal, the notification issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Act, declaring NDFB as an unlawful association dated 23-11-2002. The notification was accompanied by a resume, giving the aims and objects of the NDFB as also the facts on which the grounds in the notification under Section 3 were based, as required under Rule 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Rules 1968, (hereinafter referred to as "the Rules").

6. As per the resume filed, NDFB was formed on 3-4-1986, with the avowed aim and objective of liberating the Boro-inhabited areas of Assam from India and to form an independent and sovereign Bodoland through armed struggle. Copy of the Constitution of NDFB has also been produced on record. The principles and ideology of NDFB as per the Constitution Ex. PW1/A1 are (i) to liberate Bodoland from the Indian expansionism and occupation; (ii) to free the Boro nation from the colonialist exploitation, oppression and domination; (iii) to establish a Democratic Socialist Society to promote liberty, equality and fraternity; and (iv) to uphold the integrity and sovereignty of Boro-land.

The NDFB had been declared an unlawful association on 23.11.1992 under the Act. The ban had been subsequently reimposed on 23-11-1994, 23-11-1996, 23-11-1998 and 23-11-2000, followed by the present notification issued on 23-11-2002.

7. The Central and State Government of Assam filed evidence by way of affidavits of the following persons to support the case, as set up in para 6 above :

PW1. Mr. S. K. Roy, Joint Secretary to the Government of Assam, Political Department, Guwahati.

PW2. Sri Pratul Ch. Phukan, Superintendent of Police, Special Operation Unit, Government of Assam, Dispur, Guwahati.

PW3. Mr. B. B. Chetri, Superintendent of Police, Barpeta District.

PW4. Mr. Khabir Ahmed, Superintendent of Police, Darrang District.

PW5. Mr. R. Vijay Krishna Supdt. of Police, Kokrajhar

District.

PW6. Mr. Satyen Gogoi, Superintendent of Police, Sonitpur, Tejpur.

PW7. Mr. M. Agrawal, Superintendent of Police, Kamrup(rural)

PW8. Mr. Amarendra Borgohain Supdt. of Police, Bongaigaon District.

PW9. Mr. P. C. Borodoloi, Supdt. of Police, Dhubri. PW10. Sri Sarat Kumar Phukan Supdt. of Police, Nalbari. PW11. Mr. A. K. Goyal, Director North-East in the Ministry of Home Affairs.

8. It is the case of the Central Government that NDFB since its inception has been indulging in large scale terrorist and subversive act in the Bodo-inhabited areas within the District of Darrang, Sonit-pur, Kokrajhar, Bongaigaon, Nalbari, Barpeta, Dhubri and Kamrup causing widespread panic and feeling of insecurity among the non-tribal population and also Bodos opposed to the secessionist ideology of the NDFB. Even during the currency of the ban period, the NDFB continued its secessionist activities by stepping up its acts of terrorist violence including attacks on and killing of Army/Police/Security Forces personnel and law abiding civilians, looting of arms and ammunitions from security forces personnel,

destruction of public properties. NDFB is known to have established a number of camps in Bangladesh inside Khagrasari District and in Bhutan opposite Darrang, Nalbari, Kokrajhar and Barpeta districts of Assam, where it has trained up more than a thousand members of its cadre. It is stated that during the year 2000, following decision of the Bhutan Government not to allow the outfit to carry on their terrorist activities from the soil of Bhutan, NDFB got antagonized. It went on a killing spree in the State, gunning down 13 Bhutanese including one Nepali of Bhutanese origin. Trucks were also set ablaze.

9. During the period 23-11-2000 to 30-6-2002, there were 327 incidents of violence attributable to NDFB outfit from the State of Assam. NDFB activists killed 275 persons out of which 24 were army/police and security personnel and 251 civilians. 147 persons were injured. There were cases of kidnapping of tea garden personnel numbering 43 out of whom 22 were subsequently released, 11 were killed and 10 persons still happen to be in captivity. NDFB cadres have acquired and are in possession of sophisticated weapons and continue to recruit fresh cadres. NDFB followed the strategy of ethnic cleansing by indulging in killing of immigrant Muslims, Bengali Hindus, Nepalis and Adivasis in the Boro areas with a view to compel them to leave their settlements. It is the case of the Central Government that NDFB has been aligning itself with ULFA and other terrorist and secessionist organizations to disrupt the sovereignty and integrity of India.

10. During the period 23-11-2000 to 30-6-2002, the NDFB has been attributed with following violent activities :

- (i) 275 killings.
- (ii) Kidnapping for ransom and extortion with a view to finance its activities;
- (iii) Recruitment of fresh cadres.
- (iv) publication of clandestine magazines, eulogizing its goals and condemning alleged exploitation by Central Government.
- (v) Exhorting its cadres to identify and attack Government machinery.
- (vi) Carnage and ethnic violence with a view to spread panic and insecurity among non-Boros, forcing them to migrate away from Boro areas.
- (vii) Establishing camps and hideouts across the country's border and obtain assistance from anti-India forces to procure arms and other assistance.

11. In the affidavit filed by Sh. A. K. Goyal, Director, North East, PW 1/1, being a substantial affidavit, filed on behalf of the Central Government, a profile of NDFB prepared by Ministry of Home Affairs, mentioned its objectives, prime office bearers and illustrative incidents of violence, as also a note on its foreign links and links with other North East extremist groups are given. The affidavit and its annexures give in detail the areas of operation, the acquisition of sophisticated weapons, the ethnic cleansing by indulging in killing of immigrants i.e. Muslims, Bengalis, Hindus, Nepalese and Adivasis in the Bodo areas, with a view to compelling them to leave their settlements. Annexure 1 of the affidavit also mentions the intelligence reports received, indicating that most of the NDFB leaders like Ranjan Daimary, Gobinda Basu-matary etc., were in camps in Bhutan or in Bangladesh, where from they were directing the operations.

12. Sh. S. K. Roy, Joint Secretary, Government of Assam, Home and Political Department was examined on oath and he proved his affidavit PW.1/1. Sh. S. K. Roy deposed that it were his official duties to collect intelligence reports, being responsible for the security of the State and to deal with unlawful associations. The information regarding activities of NDFB, as received from Superintendents of Police and district and police headquarters, was collected and statistics with regard to the criminal and unlawful activities were collated and compiled. Ex.PW.1/A1, the copy of the constitution of the NDFB. Ex.PW.1/A2 was the compilation giving the statistics of killings, kidnapping, cases of snatching of arms, district wise from the period 23-11-2000 to 30-6-2002. As per Ex. PW.1/A2, during the period 23-11-2000 to 30-6-2002, 275 persons were killed out of which 251 were civilians and 24 belonged to the police/security personnel. There were 44 incidents of kidnappings, about 147 persons were injured by NDFB cadres. The details of the incidents had also been compiled under his supervision. Ex.PW.1/3 is the note prepared, giving the details of the secessionist activities during the period of ban also. The note also gives the details of 185 incidents. He deposed that based on the information received and so collected, the State Government filed its letter dated 9-8-2002 from the Commissioner and Secretary to the Government of Assam, recommending the continuation of ban on NDFB, on account of continuance of terrorist and secessionist activities. He deposed that the information and details, as reflected in Ex.PW.1/A2, A3, A4 and A5 were correct based on the records maintained and intelligence inputs and information as received from the special branches.

13. PW.2, Sri Pratui Ch. Phukan, Superintendent of Police, Special Operation Unit, proved his affidavit PW.2/1. He deposed that he has the responsibility to collect information and give feed back to the State Government of Assam. The information, as received from other intelligence agencies, namely, IB and SSB of Central Government is analyzed and collated by him and forwarded to district units. He deposed that NDFB had been indulging in anti national activities by giving a call of boycott of Independence Day, Republic Day etc. He deposed that NDFB was active in lower Assam,

namely, Darang, Nalbari, Kokrajhar, Barpeta, Bongaigaon, Dhubri. The NDFB had been indulging in killings, extortion, kidnapping, explosion etc. The cadre of NDFB was recruited from among the young people from the Bodo dominated areas. NDFB has been aiming at several targets and at times the offences committed have an ethnic touch and non-bodo persons are made target. He stated that their cadres were being trained in Pakistan, Bangladesh and Bhutan Camps. Describing certain characteristics of NDFB, *modus operandi*, he stated that its cadres and members can generally be recognized by their features who have a look of tribals. They generally operated in small groups, using sophisticated and modern arms. At times, the involvement of NDFB was revealed either by arrested persons, eye witnesses or survivors of an incident or the statement of handicapped persons, who are released. He also deposed as to the number of killings and other incidents of violence attributable to NDFB.

14. Sh. B. B. Chetri, Superintendent of Police, Barpeta District proved his affidavit PW.3/1. Apart from describing the unlawful activities of NDFB, he submitted that the funding of NDFB was mostly by extortion. He deposed regarding an illustrative case No. 259/2001, where 150 extremists equipped with sophisticated weapons, grenade attacked Labdangguri, to capture the police post. The police post was gutted and two personnel lost their lives. NDFB flag was recovered along with burnt cap of rocket launcher and a cap of Chinese grenade. In the attack two extremists, who lost their lives were later identified as Joseph *alias* Mohan Daimari and Mithinga Daimari, who were recognized leaders of NDFB.

15. Khabir Ahmed, Superintendent of Police, Darrang District, also proved his affidavit Ex-PW4/1 and deposed with regard to the illustrative cases. In one of the cases, 5 persons were rescued and during the investigation revealed that the kidnappers belonged to NDFB and they had shifted them from one camp to another camp in Bhutan.

16. Sh. R. Vijay Krishna, Superintendent of Police, Kokrajhar District proved his affidavit Ex.PW.5/1 and deposed on the basis of record with regard to the cases in his jurisdiction. He deposed that NDFB was mainly indulging in killings, extortion and attacking the police, para military and security forces. He deposed with regard to the incident on 30-6-2001, when NDFB extremists came to the market place at Dotma and fired indiscriminately, exploding bombs, thereby resulting in death of one person and grievous injuries to the others. Two persons were also kidnapped for ransom. The kidnapped persons, who were later released, after extortion, revealed that they had been kept in jungle and the kidnappers belonged to the NDFB cadres. He also deposed about NDFB militants shooting down two persons, whom they suspected to be police informers. Sh. R. Vijay Krishna also stated that even in cases, where there was no definite and concrete evidence available of the involvement of NDFB cadre in the commission of the offences, there are salient features, from which inference of the commission of offence and involvement of NDFB can be drawn. These are (i) the occurrence of the offence in areas dominated by the Boro community where shelter and help is provided to NDFB militants; (ii) the facial and physical features, which are peculiar to the Boro community; (iii) the use of sophisticated weapons such as the AK Series assault rifles, rocket launchers and the remote improvised explosive device (IED) were the special characteristics of an attack by NDFB personnel; (iv) the practice of generally shouting slogans in favour of NDFB or leaving their flag or pamphlets.

He stated that the security forces had achieved reasonable measure of success in containing NDFB. However, any complacency would result in NDFB regrouping and strengthening itself.

17. Sh. Satyen Gogoi, Superintendent of Police, Sonitpur, Tejpur proved his affidavit Ex.PW.6/1. He deposed that in his district NDFB was the prime unlawful organisation, which was very active, followed by ULFA. He also deposed about the illustrative cases, given in the affidavit. Describing the case, a patrol party was attacked by NDFB extremists with automatic weapons and grenades. Later on, the unidentified bodies were identified as those of Kalap Boro and Menswear Bosumatory by near relations who were known members of Boro's. He also deposed as to case No.76/2000 on 30-6-2001, when one Parimal Paul had been kidnapped and on his falling sick, NDFB personnel had brought a Doctor for his treatment.

18. Similarly, Sh. M. Agrawal, Superintendent of Police, Kamrup, Sh. Amarendra Borgohain, Superintendent of Police, Bongaigaon District, Sh. P. C. Borodoloi, Superintendent of Police, Dhubri and Sh. Sarat Kumar Phukan, Superintendent of Police, Nalbari proved their respective affidavits filed by way of evidence and gave details by producing records of illustrative cases, mentioned in their respective affidavits. The illustrative incidents, in which NDFB personnel had indulged in killings including indiscriminate firing from sophisticated weapons and attacks on security forces and encounters with security forces were described. The evidence and basis of the said incidents being attributable to the NDFB personnel was also disclosed and demonstrated before the Tribunal. In case of extortion, original letters of demand, as received in one case, demanding payment of Rs. 5 crores as Bodoland tax/donation to the revolutionary fund of NDFB, were produced before the Tribunal.

19. Considering the evidence by way of affidavits, as filed on behalf of the Central Government of Sh. A. K. Goyal, PW.II with its annexures and the affidavit of Sh. S. K. Roy, Joint Secretary, State of Assam, PW.I and the statistics, information and documents and records produced before me, the Central Government has succeeded in establishing the unlawful activities of NDFB and its members. The evidence of Superintendents of Police of Districts in State of Assam and record produced has shown the numerous killings, terrorist acts attributable to NDFB and its members. The Central and

State Government established that there was sufficient cause to declare NDFB, originally known as Boro Security Force, as an unlawful association with immediate effect. The Central Government and the State Government by the affidavits, produced before the Tribunal, have demonstrated that NDFB with a view to achieve its aim and objective of liberating Boro inhabited areas of Assam from India and to form an independent and separate Bodoland through armed struggle has been indulging in unlawful activities, which has been established by the evidence produced before the Tribunal. As discussed, hereinbefore in paras 11 to 17 that NDFB is engaged in the activities of:

- (i) killings/attacking security forces, para military forces with a view to spread panic and to show its hostility to the forces deployed to protect the territorial integrity and sovereignty of India;
- (ii) killings, scaring and driving away non-Bodo population from bodo dominated areas;
- (iii) punishing bodos for resisting recruitment to cadre of NDFB;
- (iv) kidnapping and extortion to collect funds to buy arms;
- (v) close links with anti-national and other banned organisation in North-East;
- (vi) civilian killing, carnage and ethnic violence; and
- (vii) conducting its activities from camps across the border.

20. Further, considering the following factors:

- (i) the number and incident of killings, kidnapping, extortion and terrorist and unlawful activities during the period 23-11-2002 to 30-6-2002;
- (ii) the procurement of arms, ammunition and explosives from clandestine resources including foreign countries;
- (iii) establishment of training camps in Bhutan, Bangladesh; and
- (iv) continuance of attacks on army/police, security forces are clear indicators of NDFB's design to continue with its secessionist activities through armed struggle, the need for an immediate ban on the NDFB as an unlawful association was warranted to prevent the member of association from regrouping and stepping up its unlawful activities.

The Central Government in these facts was fully justified in invoking its power under Proviso 3 of Sub-section (3) to declare the association to be an unlawful one with immediate effect. Accordingly, I also hold that there was sufficient cause for declaring NDFB as an unlawful association with immediate effect under the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal, Act, 1967 as per notification No. S. O. 1224(E) dated 23-11-2002. The declaration made by the Central Government in the said notification is hereby confirmed.

Justice MANMOHAN SARIN, Unlawful Activities (Prevention) Tribunal

May 20th, 2003